वैश्विक परिपेक्ष्य में ब्रिक्स संगठन की भूमिका

डॉ संजय कुमार,

असिस्टेंट प्रोफेसर (राजनीति विज्ञान),

राजकीय महाविद्यालय अमोड़ी, चम्पावत

ईमेल – drsanjaydiwakar@gmail.com

विश्व शक्ति के रुप में इग्लैंड का दबदबा था जो द्वितीय विश्व युद्व के बाद खिसककर अमेरीका के हाथों में चली गयी। वर्ष 2007 व अन्य आर्थिक मंदियों ने अमरीका को अपनी चपेट में लेकर अमेरीकी अर्थव्यवस्था के एकक्षत्रीय प्रभुत्व को छिन्न–भिन्न कर दिया, जिससे उभरने में अमेरिका को काफी समय लगा। अमेरिका मंदी ने एशियाई देशों के हाथ में आर्थिक प्रभुत्व सौपनें में अहम भूमिका निभायी, परिणामस्वरुप आर्थिक सुढ़ता एवं तरक्की के मामले में पूर्वी देश ज्यादा रफ्तार पर हैं, और पश्चिमी देशों को पीछे छोडते़ जा रहे हैं। तेजी से बढ़ते निर्यात और मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत, चीन सहित पूरा एशिया महाद्वीप अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा आर्थिक विकास दर्ज कर रहा है। अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि विश्व अर्थव्यवस्था में उभरती हुई एशियाई अर्थव्यवस्थाऐं अन्य देशों को विकास के मामले मे पीछे छोड़ चुकी हैं।

वर्ष 2009 में प्रमुख एशियाई देशों के प्रथमाक्षरों से मिलकर बने – (BRIC) ब्राजील, रुस, भारत व चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की ,जिसकी प्रथम परिकल्पना 2001 मे ंगोल्डमैन सैश के चेयरमैन जिम ओ नील द्वारा की गयी थी। इस संगठन ने अपने प्रथम शिखर सम्मेलन 19 जून 2009 में अमेरिका व उसके यूरोपीय सहयोगियों के प्रभुत्व वाली वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के स्थान पर बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की मांग उठाई थी। 14 अप्रैल 2011 को दक्षिण अफ्रीका को भी ब्रिक का सदस्य बना दिया गया, अब यह संगठन ब्रिक्स (BRICS) के नाम से अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बना चुका है।[1]यह विकसित देशों के समूह G-8,G-20 के विश्व पर प्रभाव को सन्तुलित करने का प्रयास है। ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव–औद्योगीकृत देश है।[2]

यह संगठन न तो कोई अंतराष्ट्रीय सरकारी संगठन है और न ही किसी संधि के द्वारा स्थापित किया गया है। इसे पॉच देशों का एकीकृत प्लेटफार्म कहा जा सकता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष B-R-I-C-S क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है।[3] इस संगठन का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष किया जाता है।

वर्ष 2009 से अब तक ब्रिक्स सम्मेलन–

Sr. No.	Date(s)	Host country	Host leader	Location	Notes
1st	16 June 2009	Russia	Dmitry Medvedev	Yekaterinburg (Sevastianov's House)	
2nd	15 April 2010	Brazil	Luiz Inácio Lula da Silva	Brasília	Guests: Jacob Zuma (President of South Africa) and Riyad al-Maliki (Foreign Minister of the Palestinian National Authority)
3rd	14 April 2011	China	Hu Jintao	Sanya (Sheraton Sanya Resort)	First summit to include South Africa alongside the original BRIC countries.
4th	29 March 2012	India	Manmohan Singh	New Delhi (Taj Mahal Hotel)	The BRICS Cable announced an optical fibre submarine communications cable system that carries telecommunications between the BRICS countries.
5th	26–27 March 2013	South Africa	Jacob Zuma	Durban (Durban ICC)	
6th	14–17 July 2014	Brazil	Dilma Rousseff	Fortaleza (Centro de Eventos do Ceará)[46] Brasília	BRICS New Development Bank and BRICS Contingent Reserve Arrangement agreements signed. Guest: Leaders of Union of South American Nations (UNASUR)[47][48]
7th	8–9 July 2015	Russia	Vladimir Putin	Ufa (Congress Hall)[49]	Joint summit with SCO-EEU
8th	15–16 October 2016	India	Narendra Modi	Benaulim (Taj Exotica)	Joint summit with BIMSTEC
9th	3–5 September 2017	China	Xi Jinping	Xiamen (Xiamen International Conference Center)	Joint summit with EMDCD
10th	3–5 September 2018 (expect)	South Africa	Cyril Ramaphosa	Johannesburg	
11th	TBD 2019	Brazil			
12th	TBD 2020	Russia	Vladimir Putin	Chelyabinsk[50]	Joint summit with SCO

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS

विश्व व एशियाई देशों में ब्रिक्स की स्थिति दिन –ब– दिन मजबूत होती जा रही है ब्रिक्स बहुध्रुवीय स्थिति को मजबूती प्रदान करना चाहता है। ब्रिक्स के पास विश्व का 39.02 प्रतिशत भूभाग है।[4] जहॉं 53 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या निवास करती है, तथा विश्व की सम्पूर्ण जनसंख्या का 30 प्रतिशत (GDP) ब्रिक्स की जनसंख्या द्वारा दिया जाता है।[5] 2018 में अभी तक इन देशों की अर्थव्यवस्था (GDP) 18.6 ट्रिलियन डालर रही है जो विश्व के सम्पर्ण विश्व (GDP) का 23.2 रही। विश्व बैंक ने ब्रिक्स की विकास दर 2017 में 5.3 प्रतिशत आंका है।[6] इसके अतिरिक्त ब्रिक्स विश्व में व्यापक समतापूर्ण एवं न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना, शान्ति सौहार्द बढ़ती बेरोजगारी,भुखमरी,गरीबी,स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी समस्याओं के समाधान हेतु भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। वैश्विक आतंकवाद की समाप्ति, वैश्विक तापन,पेयजल की समस्या, बढ़ती जनसंख्या का दबाव, पर्यावरण प्रदूषण एवं अन्य ज्वलन्त समस्याओं के निराकरण में ब्रिक्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। ब्रिक्स अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों एवं संगठनों मे प्रजातांत्रिक प्रणाली के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सस्थाओं को मजबूती प्रदान करने हेतु अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था: एक दृष्टिकोण–

Country	Population (2016)[3]	Nom. GDP mil. USD (2017 est.)[51]	PPP GDP bil. USD (2017 est.)[51]	Nom. GDP per capita USD (2017 est.)[51]	PPP GDP per capita USD (2017 est.)[51]	GDP Growth (2017 est.)[52]	Foreign Exchange Reserves (2015)	Government spending	Exports[53]	Imports[54]	Literacy rate[55]	Life expectancy(years, avg.)[56][57]	HDI(2015)
Brazil	207,652,865	2,140.9 Bn	3,216.0 Bn	10,308	15,485	▲ 0.2%	$362.744 bn	$846.6 bn	$189.7 bn	$143.9 bn	92.6%	75.0	0.754 (high)
Russia	143,964,513	1,560.7 Bn	3,938.0 Bn	10,885	27,466	▲ 1.1%	$358.500 bn	$414.0 bn	$259.3 bn	$165.1 bn	99.7%	70.5	0.804 (very high)
India	1,324,171,354	2,454.4 Bn	9,489.3 Bn	1,850	7,153	▲ 7.2%	$352.131 bn	$616.0 bn	$271.6 bn	$402.4 bn	72%	68.3	0.624 (medium)
China	1,403,500,365	11,795.2 Bn	23,194.4 Bn	8,480	16,676	▲ 6.5%	$3,899.285 bn	$2,031.0 bn	$2,011.0 bn	$1,437.0 bn	96.4%	76.1	0.738 (high)
South Africa	56,015,473	317.5 Bn	761.9 Bn	5,588	13,409	▲ 1%	$47.190 bn	$95.27 bn	$83.1 bn	$85.0 bn	94.3%	62.9	0.666 (medium)
Average	627,060,914	3,653.7 Bn	8,119.9 Bn	7,422	19,041	▲ 3,2%	$1,003.970 bn	$800.574 bn	$562.94 bn	$446.68 bn	93%	70.56	0.711 (high)

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS

ब्रिक्स के लक्ष्य

ब्रिक्स के तीसरे शिखर सम्मेलन के उपरांत पॉंचो देशों ने सान्या घोषणा–पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र से ब्रिक्स की वर्तमान मान्यताओं व प्राथमिकताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। इस घोषणा मे कुल 32 बिन्दु सम्मिलित है, जिसमे से प्रमुख बिन्दु इस प्रकार है:

1. इस घोषणा मे पॉंचो देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने तथा सामान्य हित के क्षेत्रीय व वैश्विक मुदों में समन्वय को मजबूत बनाने पर बल दिया।

2. घोषणा के अनुसार ब्रिक्स व्यापक तथा मान्यता का विकास तथा एक समतापूर्ण व न्यायपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थापना है।

3. घोषणा मे विश्व शान्ति, स्थिरता ताकि विकास मे ब्रिक्स देशों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है ।

4. इन पॉचो देशों ने गैर ब्रिक्स देशों के साथ भी सामान्य हितों के मुद्दों पर सहयोग व साझेदारी की वकालत की । घोषणा मे खुलापन, एकता तथा पारस्पारिक सहायता को विकास साझेदारी का आधार बताया गया है।

5. ब्रिक्स ने वैश्विक मामलों मे विकासशील देशों की आवाज को महत्वपूर्ण स्थान देने पर बल दिया शीर्ष नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय संबधों मे प्रजातंत्र आपसी सम्मान तथा सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के तत्वों पर बल दिया।

6. घोषणा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् व अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक को प्रभावी बनाने के लिए उनमें सुरक्षा की वकालत की गई। सुधार का तात्पर्य इन संस्थाओं को अधिक प्रजातांत्रिक बनाना तथा नए विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है।

7. घोषणा में नेताओं ने समूह–20 को अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका देने की वकालत की । उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स के पॉचों देश समूह–20 के भी सदस्य हैं तथा समूह–20 विश्व की 20 सबसे बडी अर्थव्यवथाओं का समूह है।

8. सदस्य देशों नें आपस में आर्थिक व्यापार तथा निवेश के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को अधिक गहन बनाने पर बल दिया । 9, घोषणा के पॉचो देशों के मध्य विज्ञान व तकनीकी के नए क्षेत्रों मे सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

9. इसके अतिरिक्त घोषणा में आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर शीघ्र हस्ताक्षर, दोहा, व्यापार वार्ताओं तथा जलवायु परिवर्तन वार्ताओं के शीघ्र व्यापक समापन पर बल दिया।[7]

ब्रिक्स देशों की विकास दर–

Country	2000	2010	10 Y Growth	CAGR
Brazil	33	289	776%	24%
Russia	28	479	1611%	33%
India	41	300	632%	22%
China	172	2914	1594%	33%
South Africa	8	44	450%	19%
BRICS	282	4026	1328%	30%
World	2231	10786	383%	17%

Source : https://farmfolio.net/articles/brics-global-economy/

ब्रिक्स देशों की चुनौतियां

निःसंदेह ब्रिक्स तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है परन्तु इसकी सफलता की राह इतनी आसान नही है क्योंकि भारत और चीन कई मुद्दों पर आमने सामने है–

1. चीन द्वारा अपनी अधिकांश वस्तुओं को सब्सिडी के दायरे मे लाकर कम से कम मूल्य पर भारत के बाजार मे अपनी वस्तुओं को बेचना, जिससे भारत में भी सरकार पर टैक्स का दबाव कम करने का दबाव बनाया जाता है जिससे देश पर राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है।
2. चीन का दक्षिण चीन सागर व मोतियों की माला के माध्यम से हिन्द महासागर व अन्य पर हस्तक्षेप की नीति के माध्यम से भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है।
3. चीन द्वारा आतंकवाद समर्थित पाकिस्तान को आर्थिक व सैन्य सहयोग मे मद्द प्रदान करना, पाक के बन्दरगाहों को पुनर्निर्माण व आधुनिकरण करके भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है।
4. भारत चीन के सीमा विवाद आजादी से वर्तमान तक विवाद के कारण रहे है।
5. उत्तर –पूर्वी भारत के राज्यों पर साम्राज्यवादी नीति को बढ़ावा देना।
6. चीन सरकार द्वारा यूयान की विनिमय दर कम रखी गई है जिसको अमेरिका व यूरोपीय देशों ने कई बार यूयान का पुनर्मूल्यन करने की मांग उठती रही है।[8]

यद्यपि नव विकास बैंक की स्थापना 2014 में भारत की पहल पर हुई और वर्तमान में भारत के केवी कामथ इसके अध्यक्ष है। इसका मुख्यालय शंघाई में है। इसमें सभी सदस्यों द्वारा 100 अरब डालर की धनराशि जमा करेंगे परन्तु अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। गोल्डमैन सैच की ब्रिक के सम्बन्ध में अंतिम रिपोर्ट 2010 में प्रकाशित हुई जिसका शीर्षक था– **Is This A BRIC Decade?** इस रिपोर्ट के अनुसार 2000–10 के दशक में विश्व के कुल घरेलू उत्पादन में इन देशों का हिस्सा 25 प्रतिशत ही था,2010–20 में विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में इन देशों का हिस्सा 33 प्रतिशत होगा तथा सकल घरेलू उत्पाद में भी वृद्वि होगी इनका योगदान 49 प्रतिशत होगा। इन देशों में मध्यमवर्गीय जनसंख्या 2020 तक वर्तमान के 800 मिलियन से बढ़कर 1600 मिलियन हो जायेगी जिससे ये देश सामूहिक रूप से दशक के अन्त तक विकसित देशों से आगे निकल निकल जायेंगें।[9]

निष्कर्षतः कहा जा सकता है ब्रिक्स देशों में कई मुद्दों पर आपसी मतभेद होने के बावजूद भी इन देशों को निजी हितों से ऊपर उठकर कार्य करना होगा एशिया की सदी बनाने के लिए चीन को भारत के साथ सभी विवादित मुद्दों को विभिन्न शान्तिपूर्ण बैठकों के माध्यम से समाधान करना होगा इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चीन की यात्रा कर इस दिशा में सराहनीय प्रयास किया है। भारत–अमेरिका संबध को रूस को सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना चाहिए,जबकि भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के समय रूस की सेना पाकिस्तान की सेना के साथ युद्वाभ्यास कर रही थी,चीन भी पाकिस्तान के कई बन्दरगाहों को आधुनिकृत कर दक्षिण एशिया में घेरने की कोशिश कर रहा है जो ब्रिक्स के दृष्टिकोण से बिल्कुल उचित नही।अतः एक स्वार्थरहित सोच विकसित करने की जरूरत है ।

संदर्भ सूची

1- विकास रजन व कृष्णा प्रताप 'भारत और विश्व', ब्रिक्स सम्मेलन तथा इसके आर्थिक आयाम, प्रकाशन गोल्डन पीकॉक, पृ0सख्या 89।

2- श्रीशंकर पाण्डेय 'भारत की विदेश नीतिः कितनी सफल, कितनी विफल' प्रतियोगिता दर्पण,उपकार प्रकाशन,आगरा जुलाई 2016,पृष्ठ 177।

3- www.drishtiias.com

4- Paulo Roberto de Almeida* **The Brics' role in the global economy** *Trade and International Negotiations for Journalists*(Rio de Janeiro, 2009, p. 146-154; ISBN: 978-85-89534-05-5)

5- https://gshindi.com/category/international-affairs-national-issues/BRICS

6- https://en.wikipedia.org/wiki/BRICS

7- विकास रजन व कृष्णा प्रताप 'भारत और विश्व': उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नया समूह, प्रकाशन गोल्डन पीकॉक, पृ0सख्या 93–94।

8- विकास रजन व कृष्णा प्रताप 'भारत और विश्व', ब्रिक्स सम्मेलन तथा इसके आर्थिक आयाम, प्रकाशन गोल्डन पीकॉक, पृ0सख्या 89।

9- विकास रजन व कृष्णा प्रताप 'भारत और विश्व': उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नया समूह, प्रकाशन गोल्डन पीकॉक, पृ0सख्या 95।